पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 105/2019

थाना मामला संख्या-49 वर्ष-2012 थाना- महिला थाना जिला- किशनगंज से उत्पन्न

==========

रेखा देवी पत्नी शंकर गुप्ता निवासी अस्पताल रोड गांधीनगर, थाना-किशनगंज, जिला-किशनगंज।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. संगीता राय उर्फ बबली उर्फ बॉबी पत्नी प्रियनाथ राय निवासी अस्पताल रोड गांधी नगर, थाना- किशनगंज, जिला-किशनगंज
3. प्रियनाथ राय उर्फ बुद्ध राय पुत्र स्वर्गीय अनाथ बंधु राय निवासी अस्पताल रोड गांधी नगर, थाना- किशनगंज, जिला-किशनगंज

..... उत्तरवादी/ओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री रंजीत कुमार पांडे, न्यायमित्र
राज्य के लिए	:	श्री उपेंद्र कुमार, स.लो.अ.
ओ. पी. संख्या 2 और 3 के लिए	:	श्री रोहित कुमार, अधिवक्ता

==========

अधिनियम/धाराएं:

- *भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 504 सहपठित धारा 34 के साथ*
- *दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372, 377, 378, 384, 393, 401*

संदर्भित वाद:

- *मल्लिकार्जुन कोडागली बनाम कर्नाटक राज्य, (2019) 2 एससीसी 752*

- *जोसफ स्टीफन बनाम संथानासामी, (2022) 13 एससीसी 115*
- *रेनू मिश्रा बनाम झारखंड राज्य व अन्य (झारखंड उच्च न्यायालय, आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 520/2019)*

मामला:

यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका उस आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि व सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया।

याचिकाकर्ता द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया गया, जबकि प्रतिवादी की ओर से यह आपत्ति उठाई गई कि पुनरीक्षण याचिका विधिसम्मत नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता को सीधे अपील का विकल्प उपलब्ध था।

निर्णय:

- *यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। आपराधिक अपील एक वैधानिक अधिकार है, जिसे प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य विधि में प्रदत्त किया गया हो, तभी वह मान्य है। (अनुच्छेद 21)*
- *सामान्यतः आपराधिक अपील के निर्णयों को अंतिम माना जाता है, किंतु धारा 393 दं.प्र.सं. अपवादों का प्रावधान करती है, जैसे धारा 377, 378 और 384 के तहत अपील की अनुमति है। धारा 372 के प्रावधान में यह बाध्यता नहीं है कि पीड़ित केवल ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ ही अपील कर सकता है। (अनुच्छेद 21)*
- *दं.प्र.सं. की धारा 401(4) कहती है कि जहां अपील का विकल्प उपलब्ध है और वह नहीं लिया गया हो, वहां पुनरीक्षण याचिका स्वीकार्य नहीं होगी। लेकिन धारा 401(5)*

के तहत उच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह पुनरीक्षण को अपील में परिवर्तित कर दे और उस पर विचार करे। (अनुच्छेद 22)

- *चूंकि याचिकाकर्ता को बिना अनुमति सीधे अपील दायर करने का विकल्प धारा 372 के प्रावधान के तहत उपलब्ध था, किंतु इसके स्थान पर उसने पुनरीक्षण याचिका दायर की, जो धारा 401(4) दं.प्र.सं. से बाधित है। (अनुच्छेद 27)*

इसलिए, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को आपराधिक अपील में परिवर्तित किया जाता है और गुण दोष पर विचार के लिए स्वीकार की जाती है। (अनुच्छेद 28)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

मौखिक निर्णय

तारीखः 04-04-2025

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील उपस्थित नहीं हैं। इसलिए, इस न्यायालय के अनुरोध पर, श्री रंजीत कुमार पांडे, विद्वान अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से न्याय मित्र के रूप में न्यायालय की सहायता करने के लिए सहमत हो गए हैं।

2. वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पीड़िता/याचिकाकर्ता/रेखा देवी (सूचनाकर्ता) द्वारा आपराधिक अपील संख्या 16/2018 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, किशनगंज द्वारा दिनांक 02.11.2018 को पारित आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत ओ.पी. संख्या 2 और 3 द्वारा दायर आपराधिक अपील को स्वीकार

किया गया है, जिसमें श्री पुनीत कुमार तिवारी, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, किशनगंज द्वारा जी.आर. केस संख्या 1270/2012 में दिनांक 25.06.2018 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश को खारिज कर दिया गया है। केस संख्या 49/2012, जिसके तहत विद्वान ट्रायल कोर्ट ने ओ.पी. संख्या 2 और 3 को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 504 के साथ धारा 34 के तहत दोषी ठहराया।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

3. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि पीड़िता/सूचनाकर्ता/रेखा देवी, जो कि याचिकाकर्ता है, की लिखित रिपोर्ट के आधार पर किशनगंज महिला थाना कांड संख्या 49/2012 दिनांक 28.10.2012 को तीन आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिनमें ओ.पी. संख्या 2 और 3 तथा प्रमोद शर्मा शामिल हैं। आरोप के अनुसार, पीड़िता के साथ आरोपियों ने मारपीट की थी।

4. आआरोप पत्र प्रस्तुत करने और संज्ञान लेने तथा आरोप तय करने के पश्चात, मुकदमा शुरू हुआ, जिसमें विद्वान ट्रायल कोर्ट ने ओ.पी. संख्या 2 और 3 तथा प्रमोद शर्मा को दोषी पाया। हालांकि, सत्र न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 16/2018 पर अपील पर, विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अतः अपीलीय निर्णय से व्यथित होकर, पीड़िता/सूचनाकर्ता/रेखा देवी ने वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया है।

पक्षों की दलीलें

5. हालांकि, पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के दौरान, राज्य के विद्वान एपीपी और ओ.पी. संख्या 2 और 3 के विद्वान वकील द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

6. उन्होंने कहा कि धारा 372 के प्रावधान और धारा 378 सीआरपीसी के मद्देनजर याचिकाकर्ता को इस न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के बाद आपराधिक अपील दायर करनी चाहिए थी। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण धारा 401(4) सीआरपीसी के अंतर्गत आता है।

7. इसके विपरीत, विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि आपराधिक अपील संख्या 16/2018 में निचली अपीलीय अदालत द्वारा ओ.पी. संख्या 2 और 3 को बरी किए जाने के मद्देनजर, याचिकाकर्ता/सूचनाकर्ता/पीड़ित ने सही ढंग से वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया है, क्योंकि निचली अपीलीय अदालत द्वारा विवादित निर्णय पहले ही पारित किया जा चुका है और अपीलीय निर्णय के खिलाफ कोई और अपील नहीं की जा सकती। ऐसी परिस्थितियों में, पीड़ित/याचिकाकर्ता के पास एकमात्र उपाय यह था कि वह विवादित निर्णय के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण दायर करे।

विचार करें।

8. मैंने दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया। और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया।

सवाल यह है कि

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सवाल यह है कि बरी करने के अपीलीय फैसले के खिलाफ पीड़ित/याचिकाकर्ता के लिए कानूनी उपाय क्या है- क्या याचिकाकर्ता ने सही ढंग से आपराधिकपुनरीक्षण दायर किया है या उसे इस अदालत की अनुमति के साथ या उसके बिना आपराधिक अपील दायर करनी चाहिए थी।

कानूनी प्रावधान

10. बरी होने के मामले में आपराधिक अपील धारा 378 दं.प्र.सं. के तहत प्रदान की जाती है, जो निम्नानुसार हैः

"दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 दोषमुक्त किए जाने के मामले में अपील करती है।

[(1) उप-धारा (2) में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, और उप-धारा (3) और (5) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए,

(ए) जिला मजिस्ट्रेट, किसी भी मामले में, लोक अभियोजक को किसी संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश से सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है;

(बी) राज्य सरकार, किसी भी मामले में, लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के मूल या अपीलीय आदेश से उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है। [खंड (क) के तहत आदेश नहीं होने के कारण] या सत्र न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में पारित बरी करने का आदेश।]

(2) यदि बरी करने का ऐसा आदेश किसी ऐसे मामले में पारित किया जाता है जिसमें दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के तहत गठित दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा या इस संहिता के अलावा किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच करने के लिए सशक्त किसी अन्य एजेंसी द्वारा अपराध की जांच की गई है, तो केंद्र सरकार, उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन, लोक अभियोजक को एक अपील प्रस्तुत करने का भी निर्देश दे सकती है।

(क) सत्र न्यायालय को, किसी संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित बरी करने के आदेश से;

(ख) उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के मूल या अपीलीय आदेश से [जो खंड (क) के तहत आदेश या सत्र न्यायालय द्वारापुनरीक्षण में पारित बरी किए जाने का आदेश नहीं है।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत किसी भी अपील पर उच्च न्यायालय की अनुमति के अलावा विचार नहीं किया जाएगा।

(4) यदि शिकायत पर स्थापित किसी भी मामले में बरी करने का ऐसा आदेश पारित किया जाता है और उच्च न्यायालय, इस ओर से शिकायतकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर, बरी करने के आदेश से अपील

> करने के लिए विशेष अनुमति देता है, तो शिकायतकर्ता उच्च न्यायालय में ऐसी अपील प्रस्तुत कर सकता है।
>
> (5) उप-धारा (4) के तहत बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए किसी भी आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा छह महीने की समाप्ति के बाद विचार नहीं किया जाएगा, जहां शिकायतकर्ता एक लोक सेवक है, और प्रत्येक अन्य मामले में साठ दिन, बरी करने के उस आदेश की तारीख से गणना की जाती है।
>
> (6) यदि, किसी भी मामले में, बरी करने के आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए उप-धारा (4) के तहत आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो बरी करने के उस आदेश से कोई अपील उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत नहीं होगी।
>
> (जोर दिया गया)

11. उप-धारा (1), (2) और (3) पुलिस मामले में बरी होने के मामले में अपील से संबंधित हैं, जबकि उप-धारा (4) शिकायत पर स्थापित किसी भी मामले में बरी होने के खिलाफ अपील का प्रावधान करती है। उप-धारा (5) में धारा 378 के तहत ऐसी अपील दायर करने के लिए सीमा अवधि का प्रावधान है, जबकि उप-धारा (6) में प्रावधान है कि यदि उप-धारा (4) के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने से इनकार कर दिया जाता है, तो कोई अपील दायर नहीं की जा सकती है।धारा 378 (1) और 378 (2) के तहत, उच्च न्यायालय की अनुमति के अलावा उच्च न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की जा सकती है। फिर से, धारा 378 (4) दं.प्र.सं. के तहत अपील केवल शिकायतकर्ता को विशेष अनुमति देने के साथ ही उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है।

12. धारा 372 दं.प्र.सं. में यह प्रावधान है कि इस न्यायालय द्वारा या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, आपराधिक न्यायालय के किसी भी निर्णय या आदेश से कोई अपील नहीं होती है। इसका मतलब है कि कोई भी आपराधिक अपील दायर नहीं कर सकता है, सिवाय इसके कि

आपराधिक प्रक्रिया संहिता या उस समय लागू किसी अन्य कानून में प्रावधान है।यह भी इंगित करना उचित है कि वर्ष 2009 में धारा 372 में प्रावधान को जोड़ने से पहले, पीड़ित को धारा 378 (4) के तहत किसी भी आपराधिक अपील को दायर करने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं था, जो शिकायतकर्ता को उच्च न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को विशेष अनुमति देने के अधीन, शिकायत पर स्थापित किसी भी मामले में बरी होने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का अधिकार प्रदान करता है।

13. तथापि, धारा 372 दं.प्र.सं. के प्रावधान में अपराध की पीड़ित को न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त करने या कम अपराध के लिए दोषी ठहराने या अपर्याप्त क्षतिपूर्ति लागू करने के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील करने का विशेष अधिकार प्रदान किया गया है और ऐसी अपील उस न्यायालय में निहित है, जिसमें ऐसे न्यायालय के दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ आम तौर पर अपील की जाती है।

14. धारा 372 दं.प्र.सं. के प्रावधान के तहत पीड़ित द्वारा अपील दायर करने की प्रक्रिया के बारे में राय में मतभेद था। एक दृष्टिकोण के अनुसार, पीड़ित का धारा 372 दं.प्र.सं. के प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का अधिकार निरपेक्ष नहीं है।पीड़ित को धारा 378 दं.प्र.सं. की उप-धारा (3) और (4) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति या विशेष अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार, पीड़ित का धारा 372 दं.प्र.सं. के प्रावधान के तहत भी उच्च न्यायालय में अपील दायर करने का अधिकार निरपेक्ष नहीं है और पीड़ित को धारा 378 दं.प्र.सं. की उप-धारा (3) और (4) के तहत उच्च न्यायालय से अनुमति या विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है ताकि उसके समक्ष अपील दायर की जा सके।

15. हालाँकि, इस विवाद का निपटारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक निर्णय द्वारा किया गया है। **मल्लिकार्जुन कोडगली बनाम कर्नाटक राज्य,**

(2019) 2 एससीसी 752 तीन न्यायाधीशों की पीठ के बहुमत के दृष्टिकोण के अनुसार, धारा 372 दं.प्र.सं. के प्रावधान के तहत अपील दायर करने का पीड़ित का अधिकार निरपेक्ष है और पीड़ित को उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए कोई अनुमति या विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

16. मल्लिकार्जुन कोडगली मामले (ऊपर) में, पीड़ित हमले के मामले में पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिससे अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। सत्र न्यायालय द्वारा किए गए परिणामी मुकदमे में, अभियुक्त को निचली अदालत ने बरी कर दिया था। इसके बाद, पीड़ित ने बरी किए जाने के खिलाफ धारा 372 दं.प्र.सं. के प्रावधान के तहत 06.02.2009 पर उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील की। लेकिन अपील को यह मानते हुए खारिज कर दिया गया कि धारा 372 का प्रावधान 31.12.2009 से कानून में आया और घटना उस तारीख से काफी पहले हुई है। इसके बाद, पीड़ित ने धारा 378 (4) दं.प्र.सं. के तहत उच्च न्यायालय में एक और आपराधिक अपील दायर की। हालाँकि, इस अपील को भी विचारणीय नहीं माना गया, यह मानते हुए कि मामला मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत पर शुरू नहीं किया गया था। इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ, पीड़ित ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की।

17. मल्लिकार्जुन कोडगली मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 372 और धारा 378 पर बहुत विस्तार से चर्चा की और पीड़ित की अपील को स्वीकार कर लिया गया, उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया और मामले को उच्च न्यायालय को सुनवाई के लिए भेज दिया और निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर निर्णय लिया। पीड़ित द्वारा उच्च न्यायालय में दायर अपील धारा 372 दं.प्र.सं. के प्रावधान के तहत विचारणीय थी। चर्चा के दौरान, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

"73. हमारी राय में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के प्रावधान को भी एक ऐसा अर्थ दिया जाना चाहिए जो यथार्थवादी, उदार, प्रगतिशील और अपराध के पीड़ित के लिए फायदेमंद हो। इसका एक ऐतिहासिक कारण है, जिसकी शुरुआत अपराध और शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ितों के लिए न्याय के बुनियादी सिद्धांतों की घोषणा से होती है, जिसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 29-11-1985 पर 96वें पूर्ण सत्र में अपनाया गया था।

.....

74. घोषणा को व्यवहार में लाते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपराध का शिकार व्यक्ति विभिन्न अधिकारों का हकदार है। राष्ट्रीय विधान में प्रदान की गई औपचारिक प्रक्रियाओं के माध्यम से न्याय और निवारण के तंत्र तक पहुंच में, किसी मामले में बरी होने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार शामिल होना चाहिए, जैसे कि वर्तमान में हम जिस मामले से संबंधित हैं। इस संदर्भ में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के प्रावधान को अपराध के पीड़ित को लाभ पहुँचाने के लिए जीवन दिया जाना चाहिए।

75. इन परिस्थितियों में, कानून की सरल भाषा के आधार पर और कई उच्च न्यायालयों द्वारा व्याख्या किए गए और संयुक्त राष्ट्र की महासभा के प्रस्ताव के अलावा, हमारे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (डब्ल्यू.ए.) में परिभाषित एक पीड़ित अदालत के समक्ष अपील दायर करने का हकदार होगा, जिसमें आम तौर पर दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ अपील की जाती है। इससे यह पता चलता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष कोडगली द्वारा दायर अपील विचारणीय थी और इस पर अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए था।

76. जहाँ तक विशेष अनुमति प्रदान करने का प्रश्न है, एक बार फिर, हमें बार में प्रस्तुत किए गए निवेदनों से अभिभूत होने की आवश्यकता नहीं है। धारा 372 सीआरपीसी के प्रावधान की भाषा बिल्कुल स्पष्ट है, खासकर जब इसकी तुलना धारा 378(4) सीआरपीसी की भाषा से की जाती है। इस प्रावधान का पाठ बिल्कुल स्पष्ट है और यह शिकायत पर शुरू किए गए मामले में पारित बरी करने के आदेश तक ही सीमित है। "शिकायत" शब्द को धारा 2(डी) सीआरपीसी में परिभाषित किया गया है और यह मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक या लिखित रूप से किए गए किसी भी आरोप को संदर्भित करता है। इसका एफआईआर दर्ज करने या पंजीकरण से कोई

लेना-देना नहीं है, और इसलिए धारा 372 सीआरपीसी के प्रावधान के संबंध में पीड़ित के शिकायतकर्ता होने के प्रभाव पर विचार करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है।

अंतिम आदेश

77. ऊपर वर्णित कारणों से अपील की अनुमति दी और मल्लिकार्जुन कोडगली बनाम। कर्नाटक राज्य में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और मामले को 2010 के एस.सी. संख्या 49 में जिला और सत्र न्यायाधीश, बागलकोट (कर्नाटक) द्वारा पारित दिनांक- 28.10.2013 बरी करने के आदेश के खिलाफ कोडगली द्वारा दायर अपील की सुनवाई और निर्णय के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है।"

(जोर दिया गया)

18. हालांकि, **मल्लिकार्जुन कोडगली मामले** (सुप्रा) में अल्पमत के अनुसार, धारा 372 सीआरपीसी के प्रावधान के तहत अपील दायर करने के पीड़ित के अधिकार को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है। इसे सीआरपीसी की धारा 378(3) और धारा 378(4) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने से पहले उच्च न्यायालय की अनुमति या विशेष अनुमति देने का प्रावधान करता है। पीड़ित के अधिकार को आरोपी के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। जब व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है, तो आरोपी की निर्दोषता की धारणा मजबूत हो जाती है। इसलिए, उच्च न्यायालय को मामले पर गौर करना चाहिए और पहले यह तय करना चाहिए कि अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि पीड़ित द्वारा दायर अपील में ऐसी जांच न की जाए। पीड़ित को राज्य या शिकायत से ऊपर नहीं रखा जा सकता है।

19. जोसेफ स्टीफन बनाम संथानसामी, (2022) 13 एससीसी 115 इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का एक और ऐतिहासिक फैसला है, जो मल्लिकार्जुन कोडगली मामले (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा दिया

गया है। इस मामले में, आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 324 और 326 के तहत दोषी ठहराया गया था, लेकिन उन्हें धारा 307 और 506 आईपीसी के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया था। दोषियों ने सत्र न्यायालय के समक्ष दोषसिद्धि के फैसले के खिलाफ आपराधिक अपील की और पीड़िता ने धारा 307 और 506 आईपीसी के तहत आरोपों से बरी करने के फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय के समक्ष अपील की। एक सामान्य निर्णय द्वारा, अभियुक्त की अपील स्वीकार कर ली गई, जबकि पीड़िता की अपील को खारिज कर दिया गया, तथा अभियुक्त को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय से व्यथित होकर, पीड़िता ने धारा 397 सहपठित धारा 401 सीआरपीसी के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय ने धारा 401 सीआरपीसी के अंतर्गत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय को निरस्त कर दिया तथा ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय तथा सजा के आदेश को बहाल कर दिया। विचार-विमर्श के दौरान, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से टिप्पणी की:

> "8. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है। संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात, <u>इस न्यायालय के विचारार्थ निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं</u>:
>
> 8.1. (i) क्या उच्च न्यायालय द्वारा धारा 401 सीआरपीसी के अंतर्गत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त करना तथा दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में परिवर्तित करके अभियुक्त को दोषी ठहराना न्यायोचित है?
>
> 8.2. (ii) <u>ऐसे मामले में जहां पीड़ित को दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है, जैसा कि धारा 372 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रदान किया गया है तथा पीड़ित ने ऐसा कोई उपाय नहीं किया है तथा</u>

अपील नहीं की है, क्या अपील करने के स्थान पर पक्षकार/पीड़ित के कहने पर पुनरीक्षण आवेदन पर विचार किया जाना आवश्यक है?

8.3. (iii) धारा 401 सीआरपीसी की उपधारा (5) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुनरीक्षण को दोषसिद्धि में परिवर्तित करते हुए। आवेदन को अपील याचिका के रूप में स्वीकार करने और उसके अनुसार उससे निपटने के लिए, उच्च न्यायालय को न्यायिक आदेश पारित करने की आवश्यकता है?

.....

13. अब जहां तक मुद्दा (ii) का संबंध है, अर्थात, ऐसे मामले में जहां कोई अपील नहीं की गई है, हालांकि अपील संहिता के तहत है, क्या उस पक्षकार के कहने पर पुनरीक्षण आवेदन पर अभी भी विचार किया जाना है, जो अपील कर सकता था, इसका उत्तर धारा 401 सीआरपीसी की उपधारा (4) में ही निहित है। धारा 401 सीआरपीसी की उपधारा (4) इस प्रकार है:

"401. (4) जहां इस संहिता के तहत कोई अपील है और कोई अपील नहीं की गई है, उस पक्षकार के कहने पर पुनरीक्षण के माध्यम से कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, जो अपील कर सकता था।

13.1. इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि अब 2009 के बाद धारा 372 सीआरपीसी मेंपुनरीक्षण और धारा 372 सीआरपीसी में प्रावधान जोड़े जाने के बाद, पीड़ित को बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील करने का वैधानिक अधिकार है। इसलिए, ऐसे मामले में जहां कोई अपील नहीं की गई है और पीड़ित को अपील दायर करने के लिए छोड़ दिया गया है, बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ पीड़ित के कहने पर कोई पुनरीक्षण नहीं माना जाएगा। यह भी पीड़ित के हित में होगा क्योंकि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय दायरा बहुत सीमित होगा, हालांकि, अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय, अपीलीय न्यायालय के पास पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार की तुलना में व्यापक क्षेत्राधिकार होगा। इसी प्रकार, ऐसे मामले में जहां शिकायत के आधार पर किसी मामले में दोषमुक्ति का आदेश पारित किया जाता है, **शिकायतकर्ता (पीड़ित के अलावा)** धारा 378 सीआरपीसी की उपधारा (4) के तहत दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है, बशर्ते कि उच्च न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति प्रदान की गई हो।

> 13.2. जैसा कि इस न्यायालय ने मल्लिकार्जुन कोडगली बनाम कर्नाटक राज्य, (2019) 2 एससीसी 752 में देखा, जहां तक पीड़ित का संबंध है, पीड़ित को अपील के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीड़ित को धारा 372 प्रावधान के तहत अपील करने का वैधानिक अधिकार है और धारा 372 का प्रावधान शिकायतकर्ता के मामले में धारा 378 सीआरपीसी की उपधारा (4) की तरह अपील के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करने की कोई शर्त निर्धारित नहीं करता है और ऐसे मामले में जहां शिकायत पर स्थापित किसी भी मामले में बरी करने का आदेश पारित किया जाता है। बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने का पीड़ित को प्रदान किया गया अधिकार एक पूर्ण अधिकार है। इसलिए, जहां तक मुद्दा (ii) का संबंध है, अर्थात्, ऐसे मामले में जहां पीड़ित और/या शिकायतकर्ता, जैसा भी मामला हो, ने धारा 372 सीआरपीसी या धारा 378(4) के तहत बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील पेश नहीं की है और/या उसका लाभ नहीं उठाया है, पीड़ित या शिकायतकर्ता, जैसा भी मामला हो, के अनुरोध पर बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और पीड़ित या शिकायतकर्ता, जैसा भी मामला हो, को धारा 372 या धारा 378(4) के तहत प्रदत्त अपील पेश करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इसलिए मुद्दा (ii) का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।
>
> (जोर दिया गया)

20. इसलिए, **जोसेफ स्टीफन केस (सुप्रा)** और **मल्लिकार्जुन कोडागली केस (सुप्रा)** के बाद, यह तय हो गया है कि धारा 372 सीआरपीसी के प्रावधान के तहत अपील करने का पीड़ित का अधिकार पूर्ण है। पीड़ित को धारा 372 सीआरपीसी के प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय से अपील दायर करने के लिए कोई अनुमति या विशेष अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, शिकायत मामले में, शिकायतकर्ता, जो पीड़ित नहीं है, को उच्च न्यायालय से धारा 378(4) सीआरपीसी के तहत आवश्यक विशेष अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है ताकि वह उसके समक्ष अपील दायर कर सके। **जोसेफ स्टीफन केस** (सुप्रा) के पैरा 13.1 की अंतिम पंक्ति से यह स्पष्ट है। इसके अलावा, शिकायत मामले और पुलिस मामले दोनों के पीड़ित समान

रूप से धारा 372 सीआरपीसी के प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय में बिना किसी अनुमति या विशेष अनुमति के अपील दायर करने के हकदार हैं, जैसा कि धारा 378(3) और 378(4) सीआरपीसी के तहत आवश्यक है, क्योंकि धारा 372 सीआरपीसी का प्रावधान पुलिस मामले और शिकायत मामले के पीड़ित के बीच भेदभाव नहीं करता है।

21. विद्वान न्यायमित्र के इस कथन में भी कोई दम नहीं है कि अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई आपराधिक अपील नहीं की जा सकती। यहां यह बताना प्रासंगिक हो जाता है कि आपराधिक अपील का उपाय कानून द्वारा निर्मित है और जब तक दंड प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य वर्तमान कानून में इसका प्रावधान नहीं है, तब तक कोई अपील स्वीकार्य नहीं है, जैसा कि धारा 372 सीआरपीसी से स्पष्ट है और यह भी सत्य है कि धारा 393 सीआरपीसी के अनुसार, आपराधिक अपीलों में पारित निर्णय और आदेश सामान्यतः अंतिम होते हैं। लेकिन धारा 393 सीआरपीसी भी सामान्य नियम में कुछ अपवाद प्रदान करती है, जिसमें धारा 393 सीआरपीसी के सामान्य प्रावधान को धारा 377, 378 और 384 सीआरपीसी के प्रावधानों के अधीन बनाया गया है, जिसके तहत अपीलीय निर्णयों के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान किया गया है। यहां तक कि धारा 372 सीआरपीसी के प्रावधान के तहत भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पीड़ितों द्वारा केवल ट्रायल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ ही अपील दायर की जा सकती है।

22. अब, धारा 401 सीआरपीसी की उपधारा (4) और (5) लागू होती है। धारा 401(4) सीआरपीसी में प्रावधान है कि जहां आपराधिक अपील होती है और कोई अपील नहीं की जाती है, वहां अपील करने वाले पक्ष के कहने पर कोई आपराधिक पुनरीक्षण नहीं माना जा सकता। हालांकि, धारा 401(5) उच्च न्यायालय को आपराधिक पुनरीक्षण

को आपराधिक अपील के रूप में मानने और उसके अनुसार उससे निपटने में सक्षम बनाती है।

23. धारा 401 दं.प्र.सं. उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति से संबंधित है जो निम्नानुसार हैः

> "**401. उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ-**(1) मामले में किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसका अभिलेख स्वयं मंगाया गया है या जो अन्यथा उसके संज्ञान में आती है, उच्च न्यायालय अपने विवेकाधिकार पर, धारा 386,389,390 और 391 द्वारा अपील न्यायालय को या धारा 307 द्वारा सत्र न्यायालय को प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और जब पुनरीक्षण न्यायालय की रचना करने वाले न्यायाधीशों की राय समान रूप से विभाजित होती है, तो मामले का निपटारा धारा 392 द्वारा प्रदान की गई तरीके से किया जाएगा।
>
> (2) इस धारा के तहत अभियुक्त या अन्य व्यक्ति के लिए पूर्वाग्रह से कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से या अपने बचाव में वकील द्वारा सुने जाने का अवसर नहीं मिला हो।
>
> (3) इस धारा की कोई भी बात उच्च न्यायालय को बरी किए जाने के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में बदलने के लिए अधिकृत नहीं मानी जाएगी।
>
> (4) <u>जहाँ इस संहिता के तहत कोई अपील की जाती है और कोई अपील नहीं की जाती है, वहाँ उस पक्ष के कहने पर पुनरीक्षण के माध्यम से कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जो अपील कर सकता था।</u>
>
> (5) <u>जहां इस संहिता के तहत एक अपील निहित है, लेकिन किसी भी व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए एक आवेदन किया गया है और उच्च न्यायालय का समाधान है कि ऐसा आवेदन इस गलत विश्वास के तहत किया गया था कि इसमें कोई अपील नहीं है और न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है, उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदन को अपील की याचिका के रूप में मान सकता है और उसी के अनुसार व्यवहार कर सकता है।"</u>
>
> (जोर दिया गया)

24. यहां, **जोसेफ स्टीफन मामले** (सुप्रा) का संदर्भ देना फिर से लाभदायक होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित उच्च न्यायालय को निर्देश दिया

है कि वह आपराधिक पुनरीक्षण को धारा 372 सीआरपीसी के तहत आपराधिक अपील के रूप में माने और अपने स्वयं के गुण-दोष के आधार पर कानून के अनुसार इसका फैसला करे। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण को आपराधिक अपील के रूप में मानने के लिए, उच्च न्यायालय को आपराधिक पुनरीक्षण को आपराधिक अपील में बदलने के लिए न्यायिक आदेश पारित करना आवश्यक है। निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> ".....जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस प्रकार, धारा 401 सीआरपीसी की उपधारा (5) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुनरीक्षण आवेदन को अपील की याचिका के रूप में मानते हुए, उच्च न्यायालय को एक न्यायिक आदेश पारित करना आवश्यक है। हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पीड़ित होने के बावजूद भी उन्हें धारा 372 सीआरपीसी के प्रावधान के अनुसार अपील का वैधानिक अधिकार है, हम इस मामले को उच्च न्यायालय को सौंपना उचित समझते हैं ताकि पुनरीक्षण आवेदन को धारा 372 सीआरपीसी के तहत अपील की याचिका के रूप में माना जा सके और कानून के अनुसार और उनके अपने गुणों के आधार पर उनका फैसला किया जा सके। यह सभी के हित में होगा, अर्थात् पीड़ितों के साथ-साथ अभियुक्तों के भी, क्योंकि अपीलीय न्यायालय के पास पुनरीक्षण न्यायालय की तुलना में अपीलीय न्यायालय के रूप में व्यापक दायरा और अधिकार क्षेत्र होगा।"
>
> (जोर दिया गया)

25. जोसेफ स्टीफन केस (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए, **झारखंड उच्च न्यायालय ने रेणु मिश्रा बनाम झारखंड राज्य और अन्य** (आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 520/2019, दिनांक 18.04.2024 को निर्णीत) के मामले में बरी किए जाने के अपीलीय निर्णय के विरुद्ध दायर आपराधिक पुनरीक्षण को गैर-धारणीय माना। परसुडीह पी.एस. केस संख्या 309/2012 से उत्पन्न इस मामले में, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाया था। हालांकि, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के

निर्णय और सजा के आदेश को रद्द कर दिया गया था। इसलिए, सूचक ने अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के निर्णय के विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय ने **जोसेफ स्टीफन मामले** (सुप्रा) के फैसले के आलोक में आपराधिक पुनरीक्षण को गैर-धारणीय मानते हुए खारिज कर दिया और पीड़ित/याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार उचित कदम उठाने की स्वतंत्रता दी।

वर्तमान मामला

26. वर्तमान मामले की बात करें तो, मुझे पता चला है कि पीड़िता जो कि यहां याचिकाकर्ता है, की लिखित रिपोर्ट के आधार पर, किशनगंज महिला थाना मामला संख्या 49/2012 ओ.पी. संख्या 2 और 3 तथा प्रमोद शर्मा नामक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया गया था। मुकदमे के दौरान, उन्हें दोषी ठहराया गया था, लेकिन बाद में ओ.पी. संख्या 2 और 3 द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 16/2018 में, दोनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था और इसलिए, पीड़िता/याचिकाकर्ता द्वारा बरी किए जाने के अपीलीय फैसले के खिलाफ वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया गया है।

27. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों तथा बाध्यकारी न्यायिक उदाहरणों को देखते हुए, पीड़ित-याचिकाकर्ता के पास धारा 372 सीआरपीसी के प्रावधान के तहत इस न्यायालय में बिना किसी अनुमति या विशेष अनुमति के आपराधिक अपील दायर करने का विकल्प था। हालांकि, पीड़ित-याचिकाकर्ता ने वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी है। लेकिन पीड़ित-याचिकाकर्ता के पास आपराधिक अपील के उपाय की उपलब्धता को देखते हुए, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण धारा 401(4) सीआरपीसी के अंतर्गत आता है। हालांकि, धारा 401 सीआरपीसी की उप-धारा 5 इस न्यायालय को

आपराधिक पुनरीक्षण को आपराधिक अपील में परिवर्तित करने और तदनुसार उसका विचार करने तथा गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।

निष्कर्ष/आदेश

28. इसलिए, इस आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को आपराधिक अपील में परिवर्तित किया जाता है। कार्यालय को इस पुनरीक्षण याचिका में आवश्यक सुधार करने और माननीय मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से अपील को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

रविशंकर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।